



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 35]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 22, 1990/माघ 2, 1911

No. 35]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 22, 1990/MAGHA 2, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

समपहृत सम्पत्ति अपील अधिकरण

अधिमूचना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 1990

का. आ. 70(अ) -- समपहृत सम्पत्ति अपील अधिकरण, स्थापक
धोषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61)
की धारा 68ण की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते
हुए, निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् --

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम
समपहृत सम्पत्ति अपील अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1989 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं -- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपे-
क्षित न हो-

(क) "अधिनियम" से स्थापक धोषधि और मनः प्रभावी पदार्थ
अधिनियम, 1985 (1985 का 61) अभिप्रेत है।

(ख) "अपील" से धारा 68ण की उपधारा (1) के अधीन फाइल
की गई कोई अपील अभिप्रेत है।

(ग) "अपीलार्थी" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो सक्षम प्राधिकारी के
किसी आदेश से व्यथित होकर अधिकरण की अपील करता है,
और इसके अंतर्गत अपीलार्थी का प्राधिकृत प्रतिनिधि भी है।

(घ) "प्राधिकृत प्रतिनिधि" से निम्नलिखित अभिप्रेत है-

(i) किसी अपीलार्थी के संबंध में,-

(अ) कोई व्यक्ति जो अपीलार्थी का संबंधी है और जो अपीलार्थी
द्वारा अधिकरण के समक्ष हाजिर होने के लिए लिखित रूप में प्राधिकृत
किया गया है; या

(आ) भारत में किसी सिविल न्यायालय में विधि कार्य करने का
हकदार कोई विधि व्यवसायी जिसे अपीलार्थी द्वारा अधिकरण के समक्ष
हाजिर होने के लिए लिखित रूप में प्राधिकृत किया गया है; या

(इ) कोई लेखापाल जो चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट अधिनियम, 1949
(1949 का 38) की धारा 3 के अधीन गठित इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड
अकाउन्टेन्ट ऑफ इंडिया का या लागत और संकर्म अकाउन्टेन्ट अधिनियम,
1959 (1959 का 23) की धारा 3 के अधीन गठित इंस्टीट्यूट ऑफ

कास्ट एंड वक्से एकाउण्टेंट्स काफ़ इंडिया का सदस्य है तथा जिसे अपने-साथी द्वारा अधिकरण के समक्ष हाज़िर होने के लिए लिखित में प्राधिकृत किया गया है, या

(ii) किसी सक्षम प्राधिकारी के संबंध में, जो अधिकरण के समक्ष किसी कार्यवाही में एक पक्षकार है :-

(अ) केन्द्रीय सरकार का कोई विधि अधिकारी;

(आ) केन्द्रीय सरकार का सरकारी अधिवक्ता या स्थायी परामर्शी, वह किसी भी नाम से ज्ञात हो;

(इ) केन्द्रीय सरकार का कोई अधिकारी जिसे केन्द्रीय सरकार ने राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया है;

(ई) कोई विधि व्यवसायी या केन्द्रीय सरकार का अधिकारी जो केन्द्रीय सरकार या सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया है;

(उ) कोई विधि व्यवसायी या केन्द्रीय सरकार का अधिकारी जो इस प्रकार अधिसूचित या प्राधिकृत किसी व्यक्ति की ओर से कार्य कर रहा है;

(ए) "न्यायपीठ" से धारा 68ण की उपधारा (3) या (4) के अधीन गठित अधिकरण की न्यायपीठ अभिप्रेत है;

(एच) "अध्यक्ष" से अधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(छ) "सक्षम प्राधिकारी" से धारा 68ण की उपधारा (1) में परिभाषित सक्षम प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ज) "विधिक प्रतिनिधि" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो मूल व्यक्ति की सम्पदा का विधितया प्रतिनिधित्व करता है, और इसके अंतर्गत वह व्यक्ति भी है जिसे अधिकरण अपने समक्ष लम्बित कार्यवाहियों में मूल व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाला मानता है;

(झ) "सदस्य" से अधिकरण का सदस्य अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत अध्यक्ष भी है;

(ञ) किसी अपील के संबंध में "पक्षकार" से अपीलार्थी या प्रत्यर्थी अभिप्रेत है और "पक्षकारों" पद का अर्थ अपीलार्थी और प्रत्यर्थी लगाया जाएगा;

(ट) "रजिस्ट्रार से अधिकरण का रजिस्ट्रार अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ऐसा अन्य अधिकारी भी है जिसे अध्यक्ष ने रजिस्ट्रार के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत किया है;

(ठ) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(ड) "अधिकरण" से धारा 68-ब की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित समपक्षित सम्पत्ति अपील अधिकरण अभिप्रेत है।

3. अधिकरण की भाषा :- (1) अधिकरण के समक्ष सभी अभिवचन, संबंधित पक्षकारों के विकल्पानुसार, अंग्रेजी अथवा हिन्दी में हो सकते हैं।

(2) अधिकरण के सभी आदेश और अन्य कार्यवाहियाँ, अधिकरण के विकल्पानुसार अंग्रेजी या हिन्दी में हो सकते हैं।

4. अधिकरण का मुख्यालय आदि :- (1) अधिकरण का मुख्यालय नहीं दिल्ली में होगा।

(2) सभी अपीलों और अर्जियों की सुनवाई सामान्यतया मुख्यालय पर की जाएगी या अध्यक्ष के विकल्पानुसार गुम्हाई, मद्रास, कलकत्ता, इलाहाबाद या किसी अन्य स्थान पर की जा सकती है।

(3) अधिकरण का कार्यालय ऐसे अवकाश दिनों और अन्य अवकाश दिनों को बन्द रहेगा जिन दिनों केन्द्रीय सरकार के अन्य कार्यालय बंद रहते हैं।

5. अपील और अर्जियाँ दर्जित करने की प्रक्रिया :-

(1) अधिनियम की धारा 68क, धारा 68ख, धारा 68ड की उपधारा

(1) या धारा 68ड के अधीन आदेश से व्यक्ति कोई व्यक्ति अधिकरण को अपील कर सकता है और अपील का ज्ञात इन नियमों से उपाय प्रारम्भ में होगा।

(2) अपील का ज्ञापन अंग्रेजी या हिन्दी में होगा और उसमें अपील के आधार संक्षेप में और विस्तृत शीर्षों के अधीन, किसी तर्क या विवरण के बिना, दिए जाएंगे और ऐसे आधारों को क्रमानुसार संवर्गीकृत किया जाएगा।

(3) अपील का ज्ञापन और अर्जी चार प्रतियों में होगी और अपील के ज्ञापन की दशा में उसके साथ उक्त आदेश की, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, चार प्रतियाँ होंगी जिनमें से एक प्रति ऐसे आदेश की प्रमाणित प्रति या अपीलार्थी पर तामील किया गया आदेश होगी।

(4) उपनियम (1) में यथा निर्दिष्ट, इन नियमों से उपाय प्रारम्भों में क्रम सं. 5 पर दिया गया पता, अपीलार्थी का "रजिस्ट्रीकृत पता" कहलाएगा और जब तक अधिकरण को दिए गए आवेदन द्वारा, सम्यक रूप से परिवर्तन नहीं कर दिया जाता वह अपील तथा अन्य संबंधित कार्यवाहियों में, जब तक कि अपील का अंतिम रूप से अवधारण नहीं हो जाता और उसके पश्चात् तीन मास की अवधि तक, सभी सूचनाओं, आवेशिकाओं और अन्य संसूचनाओं की तामील के प्रयोजन के लिए अपीलार्थी का पता समझा जाएगा।

(5) प्रत्येक अपील में सक्षम प्राधिकारी को, जिसने वह आवेश पारित किया है, जिनके विरुद्ध अपील की गई है, एक प्रत्यर्थी के रूप में पक्षकार बनाया जाएगा।

(6) अपील का ज्ञापन अपीलार्थी द्वारा स्वयं या जहाँ एक से अधिक अपीलार्थी हैं वहाँ उनमें से किसी एक के द्वारा या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा रजिस्ट्रार के समक्ष या ऐसे अन्य अधिकारी के समक्ष जो अध्यक्ष द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा या रजिस्ट्रार को संबोधित रजिस्ट्री डाक से भेजा जा सकेगा।

स्पष्टीकरण :- इस उपनियम में, "प्राधिकृत प्रतिनिधि" पद के अंतर्गत अपीलार्थी की ओर से हाज़िर होने के लिए प्राधिकृत किए गए किसी विधि व्यवसायी या अकाउण्टेंट के विनियोजनधीन कोई व्यक्ति भी है।

(7) जब अपील का ज्ञापन रजिस्ट्री डाक से भेजा जाता है तब उक्त ज्ञापन की अधिकरण के कार्यालय पर पहुँच की तारीख अपील दाखिल करने की तारीख होगी और रजिस्ट्रार अपील के प्रत्येक ज्ञापन पर वह तारीख, पृष्ठांकित करेगा जिसको वह अधिकरण के कार्यालय पर प्रस्तुत किया जाता है या प्राप्त होता है तथा पृष्ठांकन पर हस्ताक्षर करेगा।

(8) जब अपील अपीलार्थी पर तामील किए गए आदेश की प्राप्ति के 45 दिन की समाप्ति के पश्चात् किन्तु साठ दिन के अवकाश दाखिल की जाती है तब उसके साथ एक शपथ पत्र में समर्थित आवेदन होगा जिसमें उन तथ्यों का अधिकरण होगा जिन पर अपीलार्थी अधिकरण का यह समाधान करने के लिए निर्भर करता है कि पैनालिम दिन के भीतर अपील न दाखिल करने के लिए उसके पास पर्याप्त हेतु था।

(9) अधिकरण के समक्ष दाखिल की गई प्रत्येक अर्जी के साथ जिसके अंतर्गत रोकने की अर्जी भी है किन्तु औपचारिक या नेमा प्रकृति की अर्जियाँ नहीं हैं, एक शपथपत्र होगा और ऐसे धत्तावेजों की चार प्रतियाँ भी होंगी जिन पर वह अर्जी के समर्थन के लिए निर्भर है।

6. अपीलों को रजिस्ट्रार करने की प्रक्रिया :- (1) सक्षम प्राधिकारी के आवेशों की तामील के पैनालिम दिन के भीतर दाखिल प्रत्येक अपील ज्ञापन जो इन नियमों से उपाय प्रारम्भ में हो और अन्यथा नहीं हो, इस प्रयोजन के लिए रखी गई अर्जी में रजिस्ट्रार किया जाएगा जो अपील रजिस्ट्रार कहलाएगी और रजिस्ट्रार तत्पश्चात् अपीलार्थी या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को सूचित करेगा।

(2) यदि उपनियम (1) के अधीन दाखिल किया गया अपील शापन दृष्टिपूर्ण है किन्तु त्रुटियों गौण या तकनीकी प्रकृति की हैं तो रजिस्ट्रार अपील को अनन्तिम आधार पर रजिस्टर करेगा और अपीलार्थी को उन त्रुटियों को उनके समय के भीतर जो विनिर्दिष्ट किया जाए, दूर करने के लिए कहेंगा और ऐसी विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर त्रुटियाँ दूर कर दिए जाने पर रजिस्ट्रीकरण अनन्तिम नहीं रहेगा और अपील उपनियम (1) के अधीन निवर्तित रूप से रजिस्टर की गई समझी जाएगी।

(3) जब अपील का शापन सक्षम प्राधिकारी के आदेश की तारीख की तारीख से पैंतालीस दिन की समाप्ति पर किन्तु साठ दिन के भीतर दाखिल किया जाए और वह ग्रन्थया मही हो, तथा उसके साथ विलम्ब को माफ करने के लिए अर्जी दी गई हो, तो उसे इस बात के अधीन रहने हुए, अनन्तिम रूप से संश्लेषित और रजिस्टर किया जाएगा कि अधिकरण विलम्ब को माफ कर देगा। विलम्ब की माफ़ी के लिए आवेदन की सूचना, प्रत्यर्थी को दी जा सकती, और पक्षकारों को सुनने के पश्चात यदि यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय पर अपील दाखिल करने में पर्याप्त कारणों से निवारित रहा था तो अधिकरण विलम्ब को माफ कर देगा। तब रजिस्ट्रीकरण अनन्तिम नहीं रहेगा और अपील का निपटारा हम प्रकार किया जाएगा मानो वह उपनियम (1) के अधीन रजिस्टर की गई थी।

(4) जब अपील का शापन सक्षम प्राधिकारी के आदेश की तारीख के पश्चात पैंतालीस दिन की समाप्ति के पश्चात किन्तु साठ दिन की अवधि के भीतर, दाखिल किया जाता है और उसके साथ विलम्ब को माफ करने की अर्जी नहीं दी जाती है तो रजिस्ट्रार अपील का अनन्तिम रूप से रजिस्टर कर सकता है और अपीलार्थी से ऐसी अवधि के भीतर जो विनिर्दिष्ट की जाए विलम्ब को माफ करने की अर्जी दाखिल करने के लिए कह सकता है और इस प्रकार की अर्जी प्राप्त होने की दशा में उसका निपटारा हम प्रकार किया जाएगा मानो वह अपील के शापन के साथ प्राप्त हुई थी और तब अपील का निपटारा उपनियम (3) में विहित रूप से किया जाएगा।

(5) यदि इस निमित्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर त्रुटियों को दूर नहीं किया जाता है या विलम्ब को माफ़ी के लिए अर्जी दाखिल नहीं की जाती है तो मामला अधिकरण के समक्ष उनके आदेश के लिए रखा जाएगा।

(6) यदि अपील के शापन को सारभूत विनिर्दिष्टियों में त्रुटि हो तो रजिस्ट्रार उन त्रुटियों को अपीलार्थी को विनिर्दिष्ट कर सकता है या लिखित रूप में उन त्रुटियों को संसूचित कर सकता है। रजिस्ट्रार से अपील का शापन प्राप्त हो जाने पर अपीलार्थी उनकी प्राप्ति के तीस दिन के भीतर त्रुटियों को सम्पूर्ण रूप से दूर करके अपील शापन को पुनः प्रस्तुत कर सकता है या उस दशा में जब अपील का शापन उसे वापस नहीं लौटाया जाता है और त्रुटियाँ केवल संसूचित की जाती हैं वह स्वयं या काउंसल की मार्फत रजिस्ट्रार के समक्ष हाजिर हो सकेगा और उन त्रुटियों को तीस दिन के भीतर दूर कर सकेगा। अल्पसंख्यक प्रस्तुत किया गया अपील का शापन सही पाए जाने पर रजिस्टर किया जा सकेगा।

(7) जब अपील का शापन प्रथम दृष्टया सक्षम प्राधिकारी के अपीलार्थी पर आदेश की तारीख की तारीख से साठ दिन से अधिक के पश्चात प्राप्त किया गया प्रतीत हो तो अपील रजिस्टर नहीं की जाएगी अपितु रजिस्ट्रार अपीलार्थी से यह हेतुक दणित करने की अपेक्षा करेगा कि अपील कालातीत होने के कारण खारिज क्यों नहीं कर दी जाए।

(8) विलम्ब की माफ़ी का प्रत्येक आवेदन और समय के पश्चात प्राप्त किया गया प्रत्येक अपील का शापन अवश्य के समक्ष रखा जाएगा जो आवेदन अपील का अधिकरण के समक्ष उनके आदेशों के लिए रखे जाने का निर्देश वे मंगेगा।

7. अपील के रजिस्ट्रीकरण के पश्चात प्रक्रिया.— (1) अपील रजिस्ट्रीकृत हो जाने के पश्चात अपील के शापन और उसके उपायों की एक

प्रति यथाशीघ्र सक्षम प्राधिकारी को या तो रसीदी रजिस्ट्री डाक भेजकर या संवेगवाहक के माध्यम से तामील की जाएगी तथा पक्षकारों से सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर या ऐसी अवधि के भीतर जो अनुशात की जाए अपना पेपर बुक दाखिल करने की अपेक्षा की जाएगी।

(2) प्रत्येक पक्षकार अपनी पेपर बुक की चार प्रतियाँ दाखिल करेगा—

- (i) जो सुपाठ्य रूप से टाइप की गई या किसी यांत्रिक साधन से अन्यथा तैयार की गई होगी ;
- (ii) जिसमें वे सभी दस्तावेज होंगे जिन पर पक्षकार सुनवाई के अनुक्रम में निर्भर रहना चाहता है ;
- (iii) जिसमें केवल ऐसे दस्तावेजों और ऐसी सामग्री होगी जो सक्षम प्राधिकारी के समक्ष विनिर्दिष्ट या प्रस्तुत की गई हो या जिस पर निर्भर किया गया हो ;
- (iv) जिसके पृष्ठ क्रमानुसार संख्यांकित होंगे ; और
- (v) जिसमें पूरी विषय सूची या विषय सारणी होगी।

(3) यदि उपनियम (2) में निर्दिष्ट पेपर बुक में कोई दस्तावेज अंग्रेजी या हिन्दी से भिन्न किसी भाषा में है तो उसका अंग्रेजी या हिन्दी में सही अनुबाध भी जोड़ा जाएगा।

(4) पक्षकारों को रसीदी रजिस्ट्री डाक से या संवेगवाहक के माध्यम से सूचना तामील करके अपील की सुनवाई की तारीख और समय सूचित किया जाएगा :

परन्तु यदि पक्षकार या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि अधिकरण के समक्ष हाजिर है तो अधिकरण उन्हें अपील की सुनवाई की तारीख और समय मौखिक रूप से सूचित कर सकता है।

(5) साक्षियों या दस्तावेजों को समक्ष करने के लिए किसी अर्जी पर यदि आवश्यक हो तो, अथ पक्षकार की सूचना देने के पश्चात सुनवाई की जा सकती है।

(6) अधिकरण द्वारा जारी की जाने वाली प्रत्येक अध्यापेक्षा, निवेदन पत्र, प्राधिकार पत्र या लिखित सूचना पर रजिस्ट्रार हस्ताक्षर करेगा और वह रसीदी रजिस्ट्री डाक से या संवेगवाहक के माध्यम से भेजा जाएगा या भेजी जाएगी।

8. अपीलों की संयुक्त सुनवाई और निष्पादन :— अधिकरण जब भी वह ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझता है एक या अधिक अपीलों की सुनवाई एक साथ कर सकता है और उनका निपटारा एक ही आवेदन द्वारा कर सकता है।

9. अपील के आधार :— अपीलार्थी अधिकरण की दृष्टिकोण से किता ऐसे किसी आधार के समर्थन में जो अपील के कारण शापन में अधिकृत नहीं है, न तो तर्क करेगा और न ही उसे सुना जाएगा, किन्तु अधिकरण, अपील का विनिश्चय करने में केवल उन आधारों तक स्वयं को सीमित नहीं रखेगा जिन्हें अपील के शापन में उपलब्ध किया गया है या जिनके लिए इस नियम के अधीन अधिकरण की अनुमति प्राप्त की गई है :

परन्तु अधिकरण अपना विनिश्चय अपील के शापन में उल्लिखित आधारों से भिन्न किसी ऐसे आधार पर तब तक नहीं करेगा जब तक कि उस पक्षकार को जो उससे प्रभावित हो सकता है, उस आधार पर सुनवाई का उचित अवसर प्रदान नहीं कर दिया जाता है।

10. स्थगना :— अधिकरण किसी मामले की सुनवाई किसी अन्य तारीख के लिए स्थगित कर सकेगा और पक्षकारों या उनको और से हाजिर होने वाले उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों की मामले की सुनवाई की आगामी तारीख और स्थान में सूचित करेगा।

11. अपीलार्थी के व्यक्तिगत के कारण अपील का खारिज किया जाना — यदि सुनवाई के लिए नियत दिन या किसी अन्य दिन जिस को सुनवाई स्थिति की गई हो अपीलार्थी या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि अपील की सुनवाई के लिए पुकार किए जाने पर हाजिर नहीं होता है तो अधिकरण व्यक्तिगत के कारण अपील को खारिज कर सकता है या उसकी एक पक्षीय सुनवाई के लिए अग्रसर हो सकता है।

परन्तु जहाँ अपील व्यक्तिगत के कारण खारिज की गई हो या उस पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई हो और अपीलार्थी तत्पश्चात् हाजिर हो जाता है और अधिकरण का यह समाधान कर देता है कि सुनवाई के लिए पुकार किए जाने के समक्ष उसके हाजिर न होने के लिए पर्याप्त हेतुक या तो अधिकरण प्रत्यर्थी को सूचना देने के पश्चात् खारिजी के आदेश को या एक पक्षीय कार्यवाही को अग्रस्त कर सकता है और अपील को उसके मूल संख्या पर पुनः रख सकता है।

12. मृत्यु, विवाहियापन आदि की अपील पर प्रभाव — (1) अपीलार्थी की मृत्यु या उसके विवाहिया व्यापनिर्णीत किए जाने मात्र के कारण अपील उपपन्न नहीं होगी।

(2) अधिकरण मृत अपीलार्थी के विधिक प्रतिनिधि द्वारा इस निमित्त आवेदन किए जाने पर उसे पक्षकार बना सकता है और अपील में आगे कार्यवाही कर सकता है।

(3) यदि अपीलार्थी की मृत्यु के नब्बे दिन के भीतर या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो अधिकरण मृत अपीलार्थी के विधिक प्रतिनिधि को अभिलेख पर लाने के लिए अनुमति करे, कोई आवेदन नहीं किया जाता है तो अपील उपपन्न हो जाएगी।

(4) अपीलार्थी के विवाहिया हो जाने पर अपील लेनदारों के फायदे के लिए समनुदेशिता या रिसीवर द्वारा जारी रखी जा सकेगी तथा यदि समनुदेशिता या रिसीवर अपील को जारी रखने में असफल रहता है तो अधिकरण स्वप्रेरणा से या प्रत्यर्थी के आवेदन पर अपील को खारिज कर सकता है।

13. अधिकरण द्वारा मामले का प्रतिप्रेषण — (1) अधिकरण, जब भी यह आवश्यक समझे, सक्षम प्राधिकारी के किसी आदेश को अग्रस्त कर सकता है और मामले को ऐसे निदेशों को ध्यान में रखते हुए जैसे वह वे, पुनः अवधारण के लिए सक्षम प्राधिकारी को प्रतिप्रेषित कर सकता है।

(2) अधिकरण यदि कार्यवाही के किसी अनुक्रम पर आवश्यक समझता है तो, ऐसे विषयों पर, जो वह विनिश्चित करे, सक्षम प्राधिकारी से रिपोर्ट या उसके निष्कर्ष मांग सकता है।

(3) उपनियम (2) के अर्थात् निश्चित किसी ऐसी रिपोर्ट या निष्कर्ष की प्रति पक्षकारों को दी जाएगी और इसके पूर्व कि अधिकरण अंतिम आदेशों की घोषणा करे उन पर पुनः सुना जाएगा।

14. अधिकरण के समक्ष अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करना — (1) अपील के पक्षकार, अधिकरण के समक्ष अतिरिक्त साक्ष्य, चाहे वह मौखिक हो या दस्तावेजी, प्रस्तुत करने के हक्कार नहीं होंगे किन्तु निम्नलिखित दस्तावेजों में अधिकरण ऐसा साक्ष्य या दस्तावेज प्रस्तुत करने या साक्षियों की परीक्षा करने की अनुमति दे सकता है, अर्थात् —

(क) जहाँ सक्षम प्राधिकारी ने, जिसके आदेश के विरुद्ध अपील दाखिल की गई है, किसी ऐसे साक्ष्य को ग्रहण करने से इंकार कर दिया हो जो ग्रहण किया जाना चाहिए, या

(ख) जहाँ अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने की प्रार्थना करने वाला पक्षकार यह सिद्ध कर देता है कि सम्यक् तत्परता बरते जाने पर भी ऐसा साक्ष्य उनकी जानकारी में नहीं था या, सम्यक् तत्परता बरते जाने के पश्चात् भी वह उस समय उनके

द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था जब वह आदेश पारित किया गया था जिसके विरुद्ध अपील की गई है, या

(ग) जब अधिकरण उसे आदेश घोषित करने में समर्थ बनाने के लिए या किसी अन्य तात्त्विक कारण से, कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने या किसी साक्षी का परीक्षण करने की अपेक्षा करता है, या

(घ) जब अधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि सक्षम प्राधिकारों ने मामले का विनिश्चय अपीलार्थी को उस विषय पर साक्ष्य प्रस्तुत करने का उचित अवसर प्रदान किए बिना किया है।

(2) अधिकरण जहाँ भी अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति देता है वहाँ वह उसे ग्रहण करने के कारणों को लेखबद्ध करेगा।

15. अपील की सुनवाई — अपील की सुनवाई के प्रयोजनों के लिए अधिकरण को बैंक का स्थान खुला न्यायालय समझा जाएगा जहाँ साधारणतः जनता की पहुँच वहाँ तक हो सकेगी जहाँ तक वहाँ उनके लिए सुविधाजनक स्थान है।

परन्तु अधिकरण, यदि वह ठीक समझता है तो, अपील की सुनवाई के किसी अनुक्रम पर यह आदेश कर सकता है कि साधारणतया जनता, या कोई व्यक्ति विशेष, अधिकरण द्वारा उपयोग किए जा रहे कक्ष या भवन में नहीं आएगा या वहाँ नहीं रहेगा या रहेगा।

16. आदेश का सुनाया जाना — सुनवाई की समाप्ति पर अधिकरण तुरन्त अपना आदेश सुना सकेगा या अपने आदेश अतिरिक्त रख सकेगा और यदि आदेश अतिरिक्त रखे जाते हैं तो अधिकरण अंतिम आदेश सुनाने के पूर्व किसी भी समय या तो स्वप्रेरणा से या किसी पक्षकार के आवेदन पर यह आदेश कर सकेगा कि अपील या अर्जी की पुनः सुनवाई की जाए।

17. आदेश का पक्षकारों को समुचित किया जाना — अधिकरण का प्रत्येक आदेश लिखित में होगा और अधिकरण के प्रत्येक अंतिम आदेश की प्रति, जो रजिस्ट्रार द्वारा मूल प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित की गई हो, पक्षकारों को, यथासंभव शीघ्र, निशुल्क दी जाएगी।

18. आदेशों पर हस्ताक्षर — (1) यदि विनिश्चय पर अधिकरण के सभी सदस्य सहमत हों तो अधिकरण के सभी सदस्यों द्वारा एक ही आदेश पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(2) जो सदस्य बहुमत के विनिश्चय से सहमत नहीं है वह बहुमत की आदेश पृथक् दे सकेगा।

(3) जहाँ राय भिन्न हों, वहाँ विनिश्चय अधिकरण के सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जाएगा।

(4) बहुमत का विनिश्चय लिखित रूप में दिया जाएगा और उस पर सभी सदस्यों द्वारा, जिनमें असहमत सदस्य भी है, हस्ताक्षर किए जाएंगे।

19. आदेशों का प्रकाशन — अधिकरण के ऐसे आदेश जिन्हें किसी प्राधिकृत रिपोर्ट या समाचारपत्रों में प्रकाशित करने के लिए उपयुक्त समझा जाता है, ऐसे प्रकाशन के लिए, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो अधिकरण अधिकृत करे, दिए जा सकेंगे।

20. कतिपय मामलों में आदेश और निदेश — इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी अधिकरण अपने आदेशों को प्रभावित करने के लिए या अपनी आदेशिकाओं का दुरुपयोग निर्धारित करने के लिए या न्याय के उद्देश्यों को सुनिश्चित करने के लिए ऐसे आदेश या निदेश दे सकेगा जिसे वह आवश्यक या समीचीन समझे।

प्रारूप

[नियम 5 और 6 देखिए]

सम्पन्न सम्पत्ति अपील अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष

अपील का, आपन

स्थापक अधिधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का संख्या 61) की धारा 68 ण (1)

19 का सं. स. अ. सं./प्र. अ. सं.

(अपील अधिकरण के कार्यालय द्वारा भरा जाएगा)

यो/अपीलार्थी -----अपीलार्थी

बनाम

(i) सक्षम प्राधिकारी, नई दिल्ली/बम्बई/कलकत्ता/मद्रास/इलाहाबाद

...प्रत्यर्थी

(i) अन्य प्रत्यर्थी, यदि कोई है

.....

1. बहू प्राधिकारी जिसके अधिन के विरुद्ध अपील की गई है।

सक्षम प्राधिकारी, नई दिल्ली/बम्बई/कलकत्ता/मद्रास/इलाहाबाद

2. अधिन की तारीख

3. अधिन की तारीख की तारीख

4. धिनिधि करें कि सुनवाई व्यक्तिगत रूप से वांछित है या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से

5. अपीलार्थी का रजिस्ट्रीकृत पता (जिसके अन्तर्गत फोन सं., यदि कोई है) जिस पर सभी सूचनाएँ, अधिनिकाएँ और संसूचनाएँ तामील की जाएगी।

6. प्रत्यर्थी का पता

(i) सक्षम प्राधिकारी नई दिल्ली/बम्बई/कलकत्ता/मद्रास/इलाहाबाद।

(ii) अन्य प्रत्यर्थी यदि कोई है

.....

7. स्थापक अधिधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 68 या धारा की उपधारा जिसके अधिन सक्षम प्राधिकारी ने अधिन किया है और जिसके विरुद्ध अपील की गई है।

8. दावाकृत अनुमोपः

(i) क्या पूरा अधिन विवादग्रस्त हैः

(ii) यदि सम्पत्ति का केवल कुछ भाग विवादग्रस्त है तो उन्हें उपावृत्त, में दीजिए।

9. अपील के अधिन (यदि स्थान पर्याप्त नहीं है तो पृथक पृष्ठ लगाइये)।

हस्ताक्षर अपीलार्थी

(हस्ताक्षर प्राधिकृत प्रतिनिधि यदि कोई है)

गत्यापन।

हैं, अपीलार्थी/अपीलार्थी का प्राधिकृत प्रतिनिधि घोषित करता है कि ऊपर जो कुछ कहा गया है वह मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है।

आज तारीख को सत्यापित किया।

स्थानः (अपीलार्थी या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर)

तारीखः

*जो लागू न होना हो उसको काट दीजिए।

टिप्पणः

1. अपील का आपन चार प्रतियों में दाखिल किया जाता चाहिए और उसके साथ उस अपील की, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, चार प्रतियाँ होंगी (जिनमें से एक उस अधिन की, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, अपीलार्थी पर तामील की गई मूल प्रति या उसकी प्रमाणित प्रति होगी)। सभी संलग्नक भी चार प्रतियों में होंगे।

- 2 अपील का ज्ञापन अंग्रेजी या हिन्दी में लिखा जाना चाहिए और उसमें अपील के आधार संक्षिप्त और विभिन्न शीर्षों के अधीन दिए जाने चाहिए तथा उसमें कोई तर्क या विवरण नहीं दिए जाने चाहिए और ऐसे आधारों को क्रमानुसार संख्यांकित किया जाना चाहिए।
- 3 यदि अपील के ज्ञापन पर अपीलार्थी द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं तो वह पर्याप्त होगा। जहाँ इन पर प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं, वहाँ इसके साथ अपीलार्थी का उनके पक्ष में प्राधिकार पत्र होगा।
- 4 अन्य व्यक्तियों के लिए कृपया स्वाक्षर अधिध और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 68 ए की उपधारा (5) के अधीन अधिमूर्चित समपहन सम्पत्ति अपील अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1989 देखें।

[फा. सं. 8 (1)/ए.टी.एफ. पी./90]

समपहृत सम्पत्ति अपील अधिकरण का निता
जी. आर. पटवर्धन, सदस्य

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

APPELLATE TRIBUNAL FOR FORFEITED PROPERTY

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd January, 1990

S.O. 70(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 68 O of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), the Appellate Tribunal for Forfeited Property hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Appellate Tribunal for Forfeited Property (Procedure) Rules, 1989.

(2) They shall come into force at once.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires—

- (a) "Act" means the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act 1985 (61 of 1985);
- (b) "appeal" means an appeal filed under sub-section (1) of section 68 O;
- (c) "appellant" means a person who, being aggrieved by an order made by the competent authority, prefers an appeal to the Tribunal, and includes the authorised representative of the appellant;
- (d) "authorised representative" means—

(i) in relation to an appellant,

- (A) any person being a relative of the appellant and authorised in writing by the appellant to attend before the Tribunal; or
- (B) a legal practitioner entitled to practise in any civil court in India, who is authorised in writing by the appellant to attend before the Tribunal; or
- (C) an accountant, being a member of the Institute of Chartered Accountants of India constituted under section 3 of the Chartered Accountants Act, 1949 (38

of 1949) or the Institute of Cost and Works Accountants of India constituted under section 3 of the Cost and Works Accountants Act, 1959 (23 of 1959), who is authorised in writing by the appellant to attend before the Tribunal, or

(ii) in relation to a competent authority who is a party to any proceedings before the Tribunal—

- (A) a Law Officer of the Central Government;
- (B) a Government Pleader or Standing Counsel to the Central Government by whatever name called;
- (C) any Officer of the Central Government notified in this behalf by the Central Government by notification in the Official Gazette;
- (D) any legal practitioner or Officer of the Central Government authorised in this behalf by the Central Government or the competent authority;
- (E) any other legal practitioner or Officer of the Central Government acting on behalf of the person so notified or authorised;

(e) "Bench" means a Bench of the Tribunal constituted under sub-section (3) or (4) of section 68 O;

(f) "Chairman" means the Chairman of the Tribunal;

(g) "competent authority" means a competent authority as defined in sub-section (1) of section 68D;

(h) "Legal representative" means a person who in law represents the estate of a deceased person, and includes any person treated by the Tribunal as representing the deceased person in the proceedings pending before the Tribunal;

(i) "member" means a member of the Tribunal and includes the Chairman;

- (i) "party" in relation to an appeal means an appellant or the respondent, and the expression "parties" shall be construed to mean the appellant and the respondent;
- (k) "registrar" means the registrar of the Tribunal and includes such other officer who is authorised by the Chairman to perform the functions of the registrar;
- (l) "section" means a section of the Act;
- (m) "Tribunal" means the Appellate Tribunal for Forfeited Property, constituted by the Central Government under sub-section (1) of sec. 68N.

3. Language of the Tribunal—(1) The pleadings before the Tribunal may, at the option of the respective parties, be in English or in Hindi.

(2) All orders and other proceedings of the Tribunal may, at the option of the Tribunal, be in English or in Hindi.

4. Headquarters of the Tribunal, etc. (1)—The Headquarters of the Tribunal shall be at New Delhi.

(2) Appeals and petitions may be heard at the Headquarters or at the discretion of the Chairman, at Bombay, Madras, Calcutta, Allahabad or any other place.

(3) The office of the Tribunal shall observe such public and other holidays as are observed by the offices of the Central Government.

5. Procedure for filing appeals and petitions.—

- (1) Any person aggrieved by an order of the competent authority made under section 68F, section 68I, sub-section (1) of section 68K or section 68L may prefer an appeal to the Tribunal; and every memorandum of appeal shall be in the form annexed to these rules.
- (2) A memorandum of appeal shall be in English or in Hindi and shall set forth concisely and under distinct heads the grounds of appeal without any argument or narrative and such grounds shall be numbered consecutively.
- (3) Every memorandum of appeal or petition shall be in quadruplicate; and in the case of a memorandum of appeal it shall be accompanied by four copies of the order appealed against, one of which shall be either a certified copy of such order or the order served on the appellant.
- (4) The address given at serial number 5 of the form appended to these rules as referred to in sub-rule (1) shall be called the "registered address" of the appellant and shall until duly changed by an application to the Tribunal be deemed to be the address of the appellant for the purpose of the service

of all notices, processes and other communications in the appeal and other connected proceedings till the final determination of the appeal and a period of three months thereafter.

- (5) In every appeal, the competent authority which passed the order appealed against, shall be impleaded as one of the respondents.
- (6) A memorandum of appeal shall be presented by the appellant in person, or when there are more appellants than one by any of them, or by his authorised representative, to the registrar or such other officer as may be authorised in this behalf by the Chairman, or may be sent by registered post addressed to the registrar.

Explanation.—In this sub-rule, the expression "authorised representative" shall include any person in the employment or a legal practitioner or an accountant who is authorised to appear on behalf of the appellant.

- (7) When a memorandum of appeal is sent by registered post, the date of receipt of the said memorandum at the office of the Tribunal shall be the date of filing of the appeal and the registrar shall on every memorandum of appeal, endorse the date on which it is presented or received at the office of the Tribunal and shall sign the endorsement.
- (8) When an appeal is presented after the expiry of forty-five days of the receipt of the order served upon the appellant but not after sixty days, it shall be accompanied by an application, supported by an affidavit, setting forth the facts on which the appellant relies to satisfy the Tribunal that he had sufficient cause for not preferring the appeal within forty-five days.
- (9) Every petition presented to the Tribunal, including a petition for stay, other than petitions of a formal or routine character, shall be accompanied by an affidavit as also four copies of such documents as are relied upon in support of the petition.

6. Procedure for registration of appeals.—

- (1) Every memorandum of appeal filed within forty-five days of service of the order of the competent authority, being in the form annexed to these rules and otherwise in order, shall be registered in a book kept for the purpose called the Register of Appeals and the registrar shall intimate the appellant or his authorised representative accordingly.
- (2) If a memorandum of appeal filed under sub-rule (1) is defective, but the defects are minor or technical in character, the registrar may register the appeal provisionally and

call upon the appellant to remove the defects within such time as may be specified and upon the defects being removed within such specified time, the registration shall cease to be provisional and the appeal shall be deemed to have been regularly registered under sub-rule (1).

(3) When a memorandum of appeal is presented after the expiry of forty five days but within a period of sixty days, after the date of service of the order of the Competent Authority, and is otherwise in order, and is accompanied by a petition for condonation of delay, it shall be numbered and registered provisionally subject to the delay being condoned by the Tribunal. Notice of the application for condonation of delay may be given to the respondent, and after hearing the parties, the Tribunal may condone the delay on being satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time. The registration of the appeal shall then cease to be provisional and the appeal dealt with as though it has been registered under sub-rule (1).

(4) When the memorandum of appeal is presented after the expiry of forty-five days but within a period of sixty days after the date of service of the order of the competent authority, and is not accompanied by a petition for condonation of delay, the registrar may register the appeal provisionally and call upon the appellant to file a petition for condonation of delay within such time as may be specified and in the event of such a petition being received, it shall be treated as having been received alongwith the memorandum of appeal and the appeal dealt within in the manner prescribed in sub-rule (3).

(5) Where the defects are not removed or a petition for condonation of delay is not filed within the time specified in that behalf, the matter shall be placed before the Tribunal for its orders.

(6) Where a memorandum of appeal is defective in material particulars, the registrar may return the memorandum of appeal specifying the defects to the appellant, or may intimate in writing those defects. On receipt of the memorandum of appeal from the registrar the appellant may within thirty days of its receipt resubmit the memorandum of appeal with defects duly removed or in case of the memorandum of appeal having not been returned to him and defects only having been intimated may appear himself or through Counsel before the registrar and remove those defects within thirty days. The memorandum of appeal submitted thereafter if found in order may be registered.

(7) When a memorandum of appeal on the face of it appears to have been filed more than sixty days after the date of service of the order of the competent authority on the appellant, the appeal shall not be registered but the appellant shall be called upon by the registrar to show cause why the appeal should not be dismissed as being out of time.

(8) Every petition for condonation of delay and every memorandum of appeal filed out of time shall be placed before the Chairman who may direct the petition/appeal to be posted before the Tribunal for its orders.

7. Procedure after registration of appeal :

(1) After an appeal is registered, one copy of the memorandum of appeal and annexures thereto shall be served, as soon as possible, on the competent authority either by registered post acknowledgement due, or through a messenger and the parties shall be called upon to file their paper-books within a period of thirty days from the date of receipt of the notice or such further time as may be allowed.

(2) Each party shall file four copies of his paper-book which shall—

(i) be legibly typed or otherwise reproduced by mechanical means ;

(ii) contain all documents upon which the party proposes to rely during the course of hearing ;

(iii) contain only such documents and material as have been referred, produced or relied upon, before the competent authority ;

(iv) have pages numbered serially ; and

(v) contain a full index or table of contents.

(3) If the paper-book referred to in sub-rule(2) contain any document in a language other than English or Hindi, a true translation thereof in English or Hindi shall be added.

(4) The parties shall be informed of the date and place of hearing of the appeal either by registered post acknowledgement due or by notice served on them through messenger :

Provided that where the parties or their authorised representatives are present before the Tribunal, it may inform them orally of the date and place of hearing of the appeal.

(5) Any petition for summoning witnesses or documents filed by a party may be heard, if necessary, after giving notice to the other party.

(6) Every requisition, direction, letter, authorisation, or written notice to be issued by the Tribunal shall be signed by the registrar and shall be sent by registered post acknowledgement due or through a messenger.

8. Joint hearing and disposal of appeals.—The Tribunal may, whenever it considers necessary or expedient to do so, hear one or more appeals together and dispose of them by a common order.

9. Grounds which may be taken in appeal.—The appellant shall not except with the leave of the Tribunal urge or be heard in support of, any ground not set forth in the memorandum of appeal but the Tribunal, in deciding the appeal, shall not be confined to the grounds set forth in the memorandum of appeal or taken with the leave of the Tribunal under this rule :

Provided that the Tribunal shall not rest its decision on any ground other than the grounds set forth in the memorandum of appeal unless the party which may be affected thereby has had a reasonable opportunity of being heard on that ground.

10. Adjournment.—The Tribunal may adjourn the hearing of any case to any other date and inform the parties or their authorised representatives appearing on their behalf of the next date and place of hearing of the case.

11. Dismissal of appeal for appellant's default.—Where on the day fixed for hearing or on any other day to which the hearing may be adjourned, the appellant or his authorised representative does not appear when the appeal is called on for hearing, the Tribunal may either dismiss the appeal for default proceed *ex parte*.

Provided that where the appeal has been dismissed for default or proceeded with *ex parte* and the appellant appears thereafter and satisfies the Tribunal that there was sufficient cause for his non-appearance when the appeal was called on for hearing, the Tribunal shall, after giving notice to the respondent, make an order setting aside the dismissal order or the *ex parte* proceedings and restoring the appeal to its original number.

12. Effect of death, insolvency, etc. on appeal.—(1) An appeal shall not abate by reason only of the death of an appellant or on his adjudication as an insolvent.

(2) The Tribunal may on an application made in this behalf by a legal representative of a deceased appellant make him a party and proceed with the appeal.

(3) When no application is made within ninety days of the death of an appellant or within such further time as the Tribunal may allow for bringing his legal representative on record, the appeal shall abate.

(4) On the insolvency of an appellant, the appeal may be continued by the assignee or the receiver for the benefit of creditors and if the assignee or the receiver fails to continue the appeal, the Tribunal may on its own motion or on an application by the respondent, dismiss the appeal.

13. Remand of case by the Tribunal.—(1) The Tribunal may, whenever it considers it necessary, set aside an order of the competent authority and remand

the case to the competent authority for fresh determination in the light of such directions as it may give.

(2) The Tribunal may if it considers necessary at any stage of the proceedings call for a report or finding from the competent authority on such matters as it may specify.

(3) A copy of any such report or finding referred to under sub-rule (2) shall be furnished to the parties and they shall be heard thereon before the Tribunal pronounces final orders.

14. Production of additional evidence before the Tribunal.—(1) The parties to an appeal shall not be entitled to produce additional evidence, whether oral or documentary, before the Tribunal, where—

- (a) the competent authority from whose order the appeal is preferred has refused to admit evidence which ought to have been admitted, or
- (b) the party seeking to produce additional evidence, establishes that notwithstanding the exercise of due diligence, such evidence was not within his knowledge or could not, after the exercise of due diligence, be produced by him at the time when the order appealed against was passed, or
- (c) the Tribunal requires any document to be produced or any witnesses to be examined to enable it to pronounce orders, or for any other substantial cause, or
- (d) the Tribunal is satisfied that the competent authority has decided the case without giving a reasonable opportunity to the appellant to adduce evidence on any point.

it may allow such evidence or document to be produced, or witness to be examined.

(2) Wherever additional evidence is allowed to be produced by the Tribunal, it shall record the reason for its admission.

15. Hearing of appeals.—The place in which the Tribunal sits for the purpose of hearing appeals shall be deemed to be an open court, to which the public generally may have access so far as the same can conveniently contain them :

Provided that the Tribunal may, if it thinks fit, order at any stage of the hearing of an appeal, that the public generally, or any particular person, shall not have access to, or be or remain in, the room or building used by the Tribunal.

16. Pronouncement of order.—After the hearing is over, the Tribunal may pronounce its order forthwith, or it may reserve its order and if the orders are reserved, the Tribunal may at any time before final orders are pronounced either on its own motion or on the application of a party order that the appeal or petition be re-heard.

17. Order to be communicated to parties.—Every order of the Tribunal shall be in writing and a copy of every final order of the Tribunal certified as a true copy by the registrar shall be supplied free of cost to the parties as early as possible.

18. Signing of orders.—(1) Where the decision of the Tribunal is unanimous, a common order shall be signed by all the Members of the Tribunal.

(2) A Member who does not concur with the decision of the majority may deliver a dissenting order.

(3) Where there is a difference of opinion, the decision shall be in accordance with the decision of the majority of Members of the Tribunal.

(4) The decision of the majority shall be reduced to writing and signed by all the members including the dissenting member.

19. Publication of orders.—Such of the orders of the Tribunal as are deemed fit for publication in any authoritative report or the press may be released for such publication on such terms and conditions as the Tribunal may lay down.

20. Orders and directions in certain cases.—Notwithstanding anything contained in these rules, the Tribunal may make such orders or give such directions as may be necessary or expedient to give effect to its orders or to prevent abuse of its process or to secure the ends of justice.

FORM

(See rules 5 and 6)

BEFORE THE APPELLATE TRIBUNAL FOR FORFEITED PROPERTY, NEW DELHI. MEMORANDUM OF APPEAL

Section 68-O(1) of the Narcotic Drugs & Psychotropic Substances Act, 1985 (Act No. 61 of 1985)

F.P.A. No. _____/M.P. No. _____ of _____ 19____
To be filled up by the office of the Appellate
Tribunal.

IN THE MATTER OF

Shri/Smt. _____ ... APPELLANT.

VS.

(i) The Competent Authority, New Delhi|
Bombay|Calcutta|Madras|Allahabad

... RESPONDENT

(ii) Other respondents, if any _____

1. Authority passing the order
appealed against.

Competent
Authority,
New Delhi|*

Bombay|
Calcutta|Madras|
Allahabad.

2. Date of the order.

3. Date of service of the order.

4. Specify whether a hearing in person or through an authorised representative is desired.

5. Registered address of the appellant (including telephone No., if any for the service of all notices, processes and communications).

6. Address of the Respondent.

(i) The Competent
Authority,
New Delhi|
Bombay|Calcutta|
Madras|Allahabad.

(ii) Other
respondents,
if any.

7. Section or sub-section of the section of Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 under which the Competent Authority passed the order and which is appealed against :

8. Relief claimed :

(i) Specify whether the entire order is disputed :

(ii) If only certain items of properties are disputed, enumerate them in an annexure :

9. Ground of appeal (Annex a separate sheet if space is not sufficient) :

(Signature of Appellant)

Signature of Authorised
Representative, if any.

VERIFICATION

I, _____ the appellant/authorised representative of the appellant, do hereby declare that what is stated above is true to the best of my knowledge, information and belief. Verified today the _____ day of _____, 19 _____.

Place : _____

Date : _____

(Signature of the appellant
or his authorised
representative)

* Strike out whatever is inapplicable.

Notes :

1. The memorandum of appeal should be filed in quadruplicate accompanied by four copies of orders appealed against (one of which shall be a certified copy of the order appealed against or the original copy of it served on the appellant). Any enclosures will also be in quadruplicate.
2. The memorandum of appeal should be written in English or in Hindi and should set forth concisely and under distinct heads the grounds of appeal and should be without any argument or narrative and such grounds should be numbered consecutively.
3. It is enough if the memorandum of appeal is signed either by the appellant or the authorised representative. Where it is signed by the authorised representative, it should be accompanied by an authorisation of the appellant in his favour.
4. For further details see the Appellate Tribunal for Forfeited Property (Procedure) Rules, 1989 notified under sub-section (5) of section 68 O of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985.

[F. No. 8(1)/ATFP/90]

By Order of the Appellate
Tribunal for Forfeited Property.
G. R. PATWARDHAN, Member

